नईदुनिया

बाजार में उतार-चढ़ाव से घबराएं नहीं, धैर्य रखें रिटेल निवेशकः सेबी प्रमुख

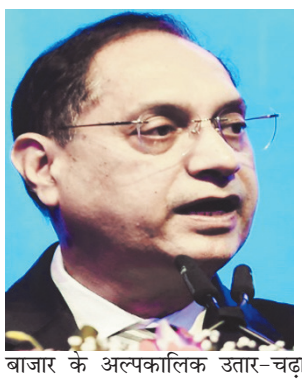

नई दिल्ली। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शनिवार को कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत के पूंजी बाजार लगातार मजबूत और व्यापक होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए सेबी प्रमुख ने रिटेल निवेशकों को सलाह दी कि वे बाजार के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। उन्होंने कहा, रिटेल निवेशकों के लिए सबसे बेहतर रणनीति धैर्य बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से, बड़े वैश्विक संकटों के बाद बाजार में फिर से सुधार देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि भारत के पूंजी बाजार आकार, विविधता और मजबूती के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं।

पांडे ने कहा, हमारे बाजार लगातार गहरे और विविध हो रहे हैं और उनकी मजबूती भी बढ़ रही है, लेकिन जैसे-जैसे बाजार का आकार और जटिलता बढ़ती है, वैसे-वैसे वे वैश्विक घटनाओं से भी अधिक प्रभावित होने लगते हैं। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, तकनीकी बदलाव और ऊर्जा संकट अनिश्चितता में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, भू-राजनीतिक तनाव आर्थिक संबंधों को आकार दे रहे हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है, जिसका प्रभाव वैश्विक पूंजी बाजारों पर भी पड़ा है।

पांडे के अनुसार, आज के वित्तीय बाजारों की एक खासियत यह है कि उनमें अस्थिरता ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जानकारी और खबरें तेजी से पूरी दुनिया में फैलती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे दौर स्थायी नहीं होते। उन्होंने कहा, एक बात स्पष्ट है कि अत्यधिक अस्थिरता के दौर हमेशा के लिए नहीं रहते। वैश्विक बाजारों में हो रहे संरचनात्मक बदलावों का जिक्र करते हुए सेबी चीफ ने कहा कि आर्थिक विभाजन, बदलते व्यापार मार्ग और तकनीक की बढ़ती भूमिका बाजारों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स के कारण बाजार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। सेबी चेयरमैन ने यह भी कहा कि आज के दौर में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और राय उससे भी तेज, जिसके कारण बाजार अक्सर खबरों और कथाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बाजार की तेजी के साथ उसकी स्थिरता भी बनी रहे। आगे की दिशा पर बात करते हुए सेबी प्रमुख ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण के लिए मजबूत बॉन्ड बाजार, संस्थागत निवेशकों की ज्यादा भागीदारी और तकनीकी नवाचार जरूरी होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी कई कदम उठा रहा है, जिनमें सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी की निगरानी और पीएआरआरवीए जैसे निगरानी सिस्टम को मजबूत करना शामिल है, ताकि बाजार में संभावित हेरफेर और गलत जानकारी का पता लगाया जा सके।

एनएमडीसी ने 2025-26 के वित्त वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया

एनएमडीसी ने रचा इतिहासः एक वित्त वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी

- एनएमडीसी ने 2025-26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन किया।
- यह भारत की पहली खनन कंपनी है, जिसने एक वित्त वर्ष में यह मील का पत्थर पार किया।
- 1978 में 10 मिलियन टन से अब 50 मिलियन टन तक उत्पादन बढ़ा।
- पिछले दशक में उत्पादन में लगभग दो-तिहाई की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- एनएमडीसी का विस्तार तेजी से हुआ, खासकर पिछले चार वर्षों में।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क (आयरन ओर) उत्पादक कंपनी एनएमडीसी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के खत्म होने से पहले ही 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही एनएमडीसी एक ही वित्त वर्ष में 50 मिलियन टन उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। सरकारी बयान के अनुसार, यह उपलब्धि न सिर्फ कंपनी की उत्पादन क्षमता को दर्शाती है, बल्कि भारत की आयरन ओर सप्लाई चेन में एनएमडीसी की मजबूत भूमिका को भी दिखाती है।

एनएमडीसी की स्थापना 1958 में भारत के लौह अयस्क संसाधनों के विकास के उद्देश्य से की गई थी। इस सरकारी कंपनी को इस्पात मंत्रालय के तहत नवरत्न सीपीएसई का दर्जा प्राप्त है। कंपनी ने 1978 में लगभग 10 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था। लेकिन, पिछले कई दशकों में उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। अब वित्त वर्ष 2025-26 में उत्पादन बढ़कर 50 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो करीब पांच गुना बढ़ोतरी को दर्शाता है। सरकारी बयान में कहा गया है कि यह उपलब्धि एनएमडीसी के धीरे-धीरे भारत की आयरन ओर सप्लाई चेन की रीढ़ बनने की यात्रा को दर्शाती है। एनएमडीसी की वृद्धि विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज हुई है। कंपनी का उत्पादन 2015 में लगभग 30 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 50 मिलियन टन तक पहुंच गया है। पिछले करीब एक दशक में उत्पादन में करीब दो-तिहाई की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि वर्तमान उत्पादन क्षमता का लगभग एक-पांचवां हिस्सा पिछले चार वर्षों में ही जोड़ा गया, जो कंपनी के इतिहास का सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है।

एनएमडीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमितवा मुखर्जी ने इस उपलब्धि को कंपनी के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा, 50 मिलियन टन उत्पादन तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है और यह एनएमडीसी 2.0 के तहत हमारे मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। जिस क्षमता को बनाने में पहले दशकों लगे, उसे हमने बेहतर कार्यान्वयन, जिम्मेदार खनन और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता के जरिए कुछ ही वर्षों में तेज कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश की सबसे बड़ी आयरन ओर उत्पादक कंपनी होने के नाते एनएमडीसी पर बड़ी जिम्मेदारी है।

कंपनी की खदानें मुख्य रूप से खनिज संपन्न राज्यों छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में स्थित हैं, जहां अत्याधुनिक और बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खनन किया जाता है। एनएमडीसी देश की आयरन ओर सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाती है। कंपनी ने कहा कि आगे भी उसका ध्यान ऑपरेशनल उत्कृष्टता, नई तकनीकों के उपयोग और जिम्मेदार खनन पर रहेगा, ताकि विकास के अगले चरण को हासिल किया जा सके।

भारत ने 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में देश में लौह अयस्क की स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना एक रणनीतिक प्राथमिकता है, जिसमें एनएमडीसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, जमाखोरी से बचें: पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराकर ईंधन जमा करने की कोशिश न करें और पेट्रोल या डीजल को ढीले या असुरक्षित कंटेनरों में भरकर न रखें, क्योंकि इससे सुरक्षा का बड़ा खतरा हो सकता है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त ईंधन का स्टॉक मौजूद है और कहीं भी कमी नहीं है।

मंत्रालय ने कहा, देश भर के रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईंधन को ढीले या अनुपयुक्त कंटेनरों में न लें और न ही स्टोर करें, क्योंकि इससे गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है। मंत्रालय के अनुसार, तमिलनाडु के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को ढीले कंटेनर में भरते हुए देखा गया था, जो कि असुरक्षित और अनुचित है। इस घटना के बाद संबंधित पेट्रोल पंप को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। साथ ही अधिकारियों ने सभी पेट्रोल पंपों और डीलरों को ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सरकार ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पैनिक बाइंग से बचने की अपील की थी, और कहा था कि देश में इन ईंधनों का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

तेल विपणन कंपनियों के अनुसार, देश के लगभग 1 लाख रिटेल आउटलेट्स में कहीं भी ईंधन खत्म होने की कोई घटना सामने नहीं आई है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता इस समय करीब 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, जिससे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन गया है। इसके अलावा सरकार ने 9 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसमें पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।

भारतः दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, घरेलू निवेशकों का बढ़ता विश्वास

नई दिल्ली।- भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और इसके साथ ही देश के शेयर बाजार में भी मजबूत मजबूती देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रही, और 2025-26 की पहली तिमाही में यह बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है। इस वैश्विक आर्थिक परिपेक्ष्य में, जबकि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं विकास दर में कमी देख रही हैं, भारत लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2026 में 6.6 प्रतिशत रह सकती है, भले ही वैश्विक अस्थिरता और अमेरिकी टैरिफ नीति का असर हो। भारत के इस आर्थिक विकास का असर पूंजी बाजार में भी साफ नजर आ रहा है। घरेलू म्यूचुअल फंड उद्योग ने 2025 में अपने एसेट बेस में 14 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की, जिससे कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट नवंबर तक रिकॉर्ड 81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 2025 में वार्षिक योगदान 3.34 लाख करोड़ रुपए रहा। भारत में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में घरेलू निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है, जो पहले विदेशी निवेशकों पर निर्भर हुआ करती थी। हालांकि, वर्तमान में केवल 15 से 20 प्रतिशत भारतीय परिवार ही इस क्षेत्र में निवेश करते हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 50 से 60 प्रतिशत तक है, जो भारत में घरेलू निवेश के विस्तार के लिए काफी संभावनाएं बताता है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स की परियोजनाओं का उद्घाटन किया रेड्डी ने

नयी दिल्ली। कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के दो दिवसीय दौरे पर कंपनी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी और डब्ल्यूसीएल की एक समीक्षा बैठक का संचालन किया। कोयला मंत्रालय की ओर से यहां शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री रेड्डी ने डब्ल्यूसीएल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आभासी माध्यम से 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री रेड्डी ने नागपुर के कामठी क्षेत्र में ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम, वानी क्षेत्र के ताडाली में स्वामी विवेकानंद इको पार्क और बल्लारपुर क्षेत्र के सास्ती ओपन कास्ट खदान में प्रारंभिग संपर्क सुविधाओं के निर्माण की परियोजना की आधारशिला भी रखी।

ये परियोजनाएं क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण और खनन कार्यों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देंगी।

उन्होंने उसके बाद कोयला उत्पादन, सुरक्षा, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की परियोजनाओं से संबंधित डब्ल्यूसीएल के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में, श्री रेड्डी ने टीम डब्ल्यूसीएल की कार्य संस्कृति और प्रदर्शन की सराहना करते हुए चालू वित्त वर्ष में बेहतर परिणामों की उम्मीद जताई। उन्होंने कोयला उद्योग के बदलते परिदृश्य में डब्ल्यूसीएल की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक के दौरान, डब्ल्यूसीएल के सीएमडी श्री हरीश दुहान ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डब्ल्यूसीएल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी. साईराम और कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और डब्ल्यूसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री रेड्डी आज मुरपार भूमिगत खदान का दौरा करेंगे वहां खदान बंद करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मंत्री जिला कलेक्टर और खदान बंद करने संबंधी सलाहकार समिति (एमसीएसी) के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में डब्ल्यूसीएल के खदान बंद करने संबंधी नोडल अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सलाहकार और स्थानीय गांवों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स रिमाइंडर मेल में गड़बड़ी पर जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। कई करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हाल ही में शिकायत की कि उन्हें एडवांस टैक्स से संबंधित ईमेल मिल रहे हैं, जिनमें कई तरह की गलत जानकारियां दी गई हैं। इसके बाद आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए करदाताओं से इन ईमेल को फिलहाल नजरअंदाज करने की अपील की है।

दरअसल पिछले एक-दो दिनों से कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को विभाग की ओर से %नज% ईमेल भेजे जा रहे थे। इन ईमेल में कहा गया था कि करदाता द्वारा किया गया एडवांस टैक्स भुगतान उनके वित्तीय लेन-देन से मेल नहीं खाता। इसके साथ ही ईमेल में उस साल के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन' का भी जिक्र किया गया था। हालांकि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स का कहना था कि इन ईमेल में जिन ट्रांजैक्शन का उल्लेख किया गया है, वे वास्तव में उनके द्वारा किए ही नहीं गए थे। यानी ईमेल में दी गई जानकारी में कई तरह की गलतियां थीं। इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने के बाद आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार दोपहर स्पष्टीकरण जारी किया। विभाग ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 (अग्रिम कर ई-अभियान) के तहत किए गए महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन से संबंधित गलत जानकारी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं द्वारा इस त्रुटि की जानकारी देने के लिए वह उनका धन्यवाद करता है और इससे हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त करता है। विभाग के अनुसार वह अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर इस समस्या को ठीक करने के लिए काम कर रहा है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक करदाता एडवांस टैक्स ई-कैंपेन से जुड़े पहले भेजे गए ईमेल को नजरअंदाज करें।

विभाग ने बताया कि ऐसे ईमेल केवल एक तरह के रिमाइंडर होते हैं, जिनका उद्देश्य करदाताओं को अपने वित्तीय लेन-देन की जानकारी की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर एडवांस टैक्स का सही तरीके से पालन करने में मदद करना है। इसके साथ ही करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने ट्रांजैक्शन्स की सही जानकारी देखने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद कंप्लायंस पोर्टल के ई-कैंपेन टैब में जाकर विवरण की जांच कर सकते हैं।

मेटा में एआई खर्च बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारीः रिपोर्ट

नई दिल्ली। अमेरिकी टेक दिग्गज मेटा प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के साथ-साथ अपने संचालन में अधिक दक्षता लाने के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी पर विचार कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा में संभावित छंटनी के तहत 20 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को निकाले जाने का विचार है। दिसंबर 2025 के अंत तक कंपनी के पास करीब 79,000 कर्मचारी थे, और इस हिसाब से लगभग 16,000 कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। हालांकि, मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने इस रिपोर्ट को केवल संभावित रणनीतियों पर आधारित अटकलें बताया है और छंटनी के पैमाने या समय पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीमों से यह आकलन करने को कहा है कि संचालन को किस तरह अधिक कुशल बनाया जा सकता है।

सीबीआई ने 228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में जय अनमोल अंबानी से की दूसरे दिन भी पूछताछ

नई दिल्ली। देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 228 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से शनिवार को दूसरे दिन फिर से पूछताछ की।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई।

यह पूछताछ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से जुड़े 228 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। इस मामले में कंपनी के पूर्व सीईओ और पूर्व पूर्णकालिक निदेशक रवींद्र सुधालकर सहित कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। मामले में जय अनमोल अंबानी भी आरोपियों में शामिल हैं। हालांकि इस संबंध में कंपनी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सीबीआई ने बीते दिन शुक्रवार को भी अनिल अंबानी के बेटे से पूछताछ की थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, जय अनमोल अंबानी से दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ की गई। अधिकारियों ने बताया कि उनसे मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से सवाल-जवाब किए गए और आगे की जांच

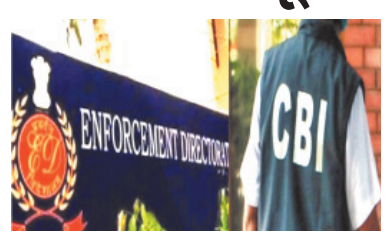

के लिए उन्हें शनिवार को भी उपस्थित रहने को कहा गया था।

सीबीआई ने इससे पहले 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्रा बैंक) की शिकायत के आधार पर की गई थी। बैंक ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने बैंक से लिया गया कर्ज वापस नहीं चुकाया, जिसके कारण वर्ष 2019 में यह खाता गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गया।

वहीं, 6 दिसंबर 2025 को सीबीआई ने इस बैंक धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया। इस मामले में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जय अनमोल अंबानी, रविंद्र सुधालकर सहित कुछ अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के जरिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को करीब 228.06 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने कुल मिलाकर 18 बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट संस्थाओं से करीब 5,572.35 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। आरोप है कि कंपनी ने इन संस्थानों को गुमराह कर लोन लिया और बाद में भुगतान नहीं किया। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

सीबीआई ने इस मामले में मुंबई स्थित विशेष सीबीआई अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद 9 दिसंबर 2025 को मुंबई में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के दो आधिकारिक परिसरों, जय अनमोल अंबानी के आवास और कंपनी के तत्कालीन निदेशक रविंद्र सुधालकर के आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है।

मिडिल ईस्ट तनाव का असरः अकासा एयर ने भी बढ़ाया किराया, 15 मार्च से लगेगा फ्यूल सरचार्ज

नई दिल्ली। एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अब अकासा एयर ने भी अपनी उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। एयरलाइन ने शनिवार को घोषणा की कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।

एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों पर 199 रुपए से लेकर 1,300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। यह अतिरिक्त शुल्क 15 मार्च 2026 को रात 12 बजकर 1 मिनट (00:01 बजे) से की जाने वाली सभी नई बुकिंग पर लागू होगा। हालांकि, इस समय से पहले बुक किए गए टिकटों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

अकासा एयर ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज प्रति सेक्टर के आधार पर लिया जाएगा, यानी उड़ान की दूरी और अवधि के अनुसार इसकी राशि अलग-अलग हो सकती है। एयरलाइन के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। चूंकि फ्यूल एयरलाइंस के संचालन खर्च का बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने से उद्योग की लागत भी बढ़ जाती है।

स्पेशल खबर प्रधानमंत्री मोदी ने हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन कर पूर्वी समुद्री तट पर माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाई

प्रधानमंत्री ने अदाणी पोर्ट्स के हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन, पूर्वी समुद्री कॉरिडोर को मिलेगी मजबूती

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अदाणी पोर्ट्स के हल्दिया बल्क टर्मिनल (एचबीटी) का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह टर्मिनल भारत के पूर्वी समुद्री तट पर माल ढुलाई की क्षमता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह टर्मिनल सूखी थोक सामग्री (ड्राई बल्क कार्गो) को संभालने के लिए बनाया गया है, जिसकी वार्षिक क्षमता 40 लाख मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) है। हुगली नदी पर बना यह पूरी तरह स्वचालित बल्क टर्मिनल है, जिसमें सीधे रेल कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे भारत के पूर्वी समुद्री कॉरिडोर में माल ढुलाई की व्यवस्था और मजबूत होगी।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा कि यह टर्मिनल अगली पीढ़ी की आधुनिक सुविधा है, जिसमें पूरी तरह मशीनीकरण और सीधे रेल निकासी की व्यवस्था है। इससे कार्गो के नुकसान को कम करने के साथ साफ, सुरक्षित और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित होगा।

उन्होंने बताया कि यह टर्मिनल पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के उद्योगों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही यह प्रधानमंत्री मोदी के लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के विजन को भी आगे बढ़ाएगा, जिसमें आधुनिक मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत के पूर्वी तट से देश के लगभग 60 प्रतिशत ड्राई बल्क

आयात होते हैं, जिनमें कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे प्रमुख संसाधन शामिल हैं। इसलिए हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के स्टील, एल्यूमिनियम और बिजली उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया है।

कंपनी के अनुसार, इस नई क्षमता से इन उद्योगों की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और माल ढुलाई में लगने वाला समय भी घटेगा।

यह टर्मिनल कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित है, जिसे एचडीसी बल्क टर्मिनल लिमिटेड द्वारा 30 साल की रियायत अवधि के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल पर विकसित किया गया है।

इस परियोजना का निर्माण 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था और निर्धारित समय के भीतर इसे पूरा कर संचालन के लिए तैयार कर दिया गया। कंपनी ने कहा कि यह अदाणी पोर्ट्स की हर बार समय पर परियोजनाएं पूरी करने की क्षमता को दर्शाता है।

निर्माण के दौरान अदाणी पोर्ट्स ने 2,000 टन की रेलवे वैगन लोडिंग सिस्टम (आरडब्ल्यूएलएस) स्थापित की है और 1.54 किलोमीटर लंबी समर्पित रेलवे लाइन को चालू किया है, जिससे जहाज से सीधे ट्रेन में कार्गो लोड किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा जेटी का नवीनीकरण, प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए उन्नत कन्वेयर सिस्टम और स्टॉकर-कम-रिक्लेमर मशीनों की स्थापना भी की गई है।

आरडब्ल्यूएलएस और समर्पित रेलवे लाइन इस टर्मिनल की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, जिनकी मदद से जहाज से उतरा माल सीधे रेलवे वैगनों में लोड होकर मुख्य रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाता है। इससे बंदरगाह पर माल के ठहराव का समय कम होगा और उद्योगों तक कच्चे माल की लागत भी घटेगी।

हल्दिया टर्मिनल को भारत के सागरमाला कार्यक्रम और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जिनका उद्देश्य मल्टीमॉडल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है।